*202. [*The questioner (Shri Ashok Nath Verma) was absent for answer, vide col. 30 infra*]

**Lack of facilities for edible oil extraction industry**

*203. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:†
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the absence of efficient means and facilities for the edible oil extraction industry in the country the quantity of oil extracted from oil seeds is considerably low as compared to the quantity of oil extracted in other countries;

(b) whether Government have ever made an assessment of the financial loss suffered by our country due to under production in this regard; and

(c) if so, the average annual rate of financial loss in this regard and whether any special efforts have been made by Government to bring efficiency in this industry and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) A number of factors like difficulty in collection of oil bearing materials lack of proper storage facilities, lack of modern processing facilities, etc. are responsible for the unsatisfactory exploitation of the available sources of oils.

(b) and (c) No assessment of the financial loss suffered by the country due to under production has been made on a scientific basis.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Mr. Chairman, Sir, my first supplementary is that we are losing something like five lakh tonnes of edible oil because our extraction processes are uneconomical and we are not getting the same amount of oil from the oil-seeds as we should do. And it is surprising that no action has been taken to modernise the processes. Now I would like to know if anything is projected to be done in this respect. That is my first supplementary.

श्री एच०के०एल० भगत : महोदय, जैसाकि मैंने पहले उत्तर में कहा है कि इसका कोई साइंटिफिक एस्टीमेट नहीं किया गया, लेकिन यह बात सत्य है जैसा आनरेबल मेम्बर जनरल अरोरा ने कहा कि जितना हमारा पोटेंशियल आइल सीड्स का एवलेबेल है आज भी, आइल सीड का बढ़ना एक बात है और बढ़ना चाहिये। उसके लिये भी कुछ स्टेप्स वगैरह सोचे गये है। कुछ टैक्नोलोजिकल मिशन बने हैं...

इसको कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इस सारे मामले के कई आस्पेक्ट्स हैं, कोई स्टेप्स वगैरह उन्होंने इसके बारे में सोचे हैं, उसके बारे में डिटेल्ज में इन्फारमेशन तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे सकते हैं लेकिन यह बात सत्य है कि हमारे इन कारणों के कारण से जितना तेल का उत्पादन किया जा सकता है उतना तेल का उत्पादन नहीं हो रहा और इस मायने में यह कहा जा सकता है, उन्होंने 5 लाख टन की फिगर कही है, कोई साइन्टिफिक फिगर नहीं, लेकिन इसमें कोई शुबहा नहीं कि तेल के उत्पादन में कई चीजों की कमियों के कारण, जो मैंने अपने उत्तर में कही है, तेल का उत्पादन हमारी जो इस वक्त भी क्षमता है, आयल सीड की प्रोडक्शन है, उसके मुताबिक जितना होना चाहिये, कम है, उस मायने में उसको लास कहा जा सकता है।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: My second supplementary is that in the month of September—it came in the *Financial Express*—a new policy had been adopted about seed imports under OGL and in that policy it was mentioned that companies which had resources and technology collaboration agreement with outside, would be permitted to import seeds under the OGL, but it was also mentioned that this was subject to the foreign suppliers agreeing to supply parent line of

*The question as actually asked on the floor of the House by Sardar Jagjit Singh Aurora.

seeds to the Indian company within a period of two years. What has happened so far, because the report of 23 November says that these companies are no greeable to provide the line of parent seeds. Is anything being done about it?

**श्री एच० के० एल० भगत** : सर, यह क्वेश्चन जो कह रहे हैं आनरेबल मैम्बर कि सीड्स के बारे में कोई आर्डर निकला है, फाइनेंशियल एक्सप्रैस में छपा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कुछ उत्तर दे सकती है। अगर आप इजाजत दें तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौजूद हैं, वह देना चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

**श्री सभापति** : वह तो हमेशा तैयार रहते हैं उत्तर देने के लिये (**व्यवधान**)

*श्री भजन लाल* : *सभापति महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो इसके बारे में जो जानकारी मुझे है, उसको मैं बता सकता हूं।*

*सभापति महोदय, नई सीड नीति हमने बनाई है और उसकी घोषणा की है। नई सीड नीति बनाने का मकसद यह है कि देश के अन्दर उत्पादन को बढ़ाया जा सके? जहां भी अच्छा सीड मिले, मोटा अनाज, फल और सब्जी, उनके बारे में हमने फैसला किया है कि ताकि जहां से भी बाहर से अच्छा सीड मिले, इस देश में आ सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके और बाकायदा उसको लाने से पहले टैस्ट किया जायेगा कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं और बाकायदा उसको आई०सी०ए०आर० यहां पर टैस्ट करेगा कि जरमिनेशन ठीक है कि नहीं, ईलडज ठीक है कि नहीं और उस पर कोई बीमारी तो आक्रमण नहीं कर सकती और उससे देश के अंदर कोई दूसरी बीमारी तो नहीं आ जायेगी। सारी बातों की अच्छी तरह से जांच करके हम उसको इजाजत देंगे ताकि देश के उत्पादन को बढ़ाया जा सके।*

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Actually, my question has not been answered. I am told that they had problems. Although they allowed it under the OGL, but the foreign companies abroad are not ready to give information about the parentage which will enable us to produce high quality within our own country.

So, Sir, this question is not being answered at all.

**श्री भजन लाल** : सभापति महोदय, मैंने अभी बताया आपको कि अभी तो हमने इस पालिसी को एनाउंस किया है पालिसी के बारे में। जब सीड आयेगा, सारी बात को देखेंगे और बाकायदा उसको टैस्ट करके बाद में उसको फील्ड में लायेंगे। जो ठीक होगा उसे लायेंगे वरना नहीं लायेंगे। आप जानना क्या चाहते हैं? (**व्यवधान**)

**सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** : आपने जो कंडीशंज लेड-डाउन की है उसके ऊपर बाहर की कम्पनियां आपको सीड देने को तैयार नहीं हैं। (**व्यवधान**)

**श्री भजन लाल** : यह तो सवाल तब आयेगा जब कोई लाने वाला तैयार न होगा, अभी भी बेशुमार डिमांड है इस बात की कि.. इतनी ऐप्लीकेशंस आ रही हैं, अकेले बाहर की कंपनियों का ही सवाल नहीं है। हमारे देश के किसान भी अगर बाहर से अच्छा सीड लेना चाहेंगे तो ला सकेंगे उसका इन्सपेक्शन करवा कर।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, the answer has still not come. I do not think he understands this.

**श्री सभापति** : अरोड़ा साहब, आपके दो सवाल हो चुके हैं। श्री शान्ति त्यागी।

**श्री शान्ति त्यागी** : श्रीमन, टेक्नालॉजी मिशन के डाइरेक्टर का यह कहना है कि देश में लगभग 36 हजार एक्सपैलर काम कर रहे हैं जो कि पुराने टाइप के हैं। इस कारण आइल केक में 12 फीसदी तेल की मात्रा रह जाती है और इस प्रकार एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान देश को साल भर में होता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि रेपसीड और सरसों की जो पिराई

होती है वह बॉर छिलका उतारे होती है, इस कारण तेल का रंग भी काला होता है और जब खाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है जो खाने में भी कालापन होता है और इससे तेल भी कम निकलता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छिलका उतारने की मशीन सरसों के लिए आप बड़ी संख्या में आगामी वर्षों में मंगाने की व्यवस्था करेंगे ?

**श्री एच०के०एल० भगत** : श्रीमन्, यह बात सही है कि हमारे देश में जो ऐक्सपैलर लगे है तेल निकालने के उसकी बहुत सी कंटेनरोज है । या तो कोल्हू से तेल निकाला जाता है, या घानी से या एक्सपैलर से निकाला जाता है । यह सही बात है कि जितना तेल निकल सकता है उतना नहीं निकलता है । उन्होंने टैक्नालाजिकल मिशन के डाइरेक्टर को कोट किया है कि उन्होंने कहा है कि इतना नुकसान होता है । उनका कोटेशन मैंने नहीं देखा, लेकिन नुकसान होता है तो इस माने में होता है कि जो फायदा हो सकता है वह नहीं हो रहा है । इस माने में वह नुकसान है । टैक्नालाजी मिशन के कई विभाग है और उनमें यह भी है कि इक्विपमेंट में सुधार किया जाए कुछ एक्सपैलर्स में सुधार लाया जाए । उन्होंने इस बारे में कई स्टेप्स लिए हैं और वे देख रहे हैं कि कितनी मशीनें किस टाइप की लगाई जाए जिससे तेल का रंग भी काला न हो । लेकिन इस टाइप की कितनी मशीनें वे कब ला रहे हैं या लगा रहे है इसकी मेरे पास सूचना नहीं है ।

**श्री सभापति** : उन्होंने छिलका उतारने का सवाल साफ तौर से पूछा है ।

**श्री भजन लाल** : श्रीमन् जहां तक छिलके और भूसी उतारने का काम है, वह दूसरों का है, हमारा तो है नहीं लेकिन मैं यहां भूसी उतारने की बात कह दूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरसो जिससे तेल बनता है, उसका दाना बहुत बारीक होता है, उस पर से छिलका उतारकर तेल बनाना संभव नहीं है । लेकिन कुछ क्वालिटी मार्केट में ऐसी आई है जिन पर काला छिलका नहीं होता है जैसा सरसों का रंग अंदर का होता है । वैसा ही है जिसे पीली सरसों कहते है ।, उसका भाव ऊंचा होता है और उसका तेल भी बढ़िया बनता है । यह सही बात है कि छिलका निकालने से कलर चेंज होता है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको हमने टैस्ट कराकर देख लिया है कि वह खाने में या सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है ।

**श्री मीर्जा इर्शाद बेग** : मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने दो बातें कही है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रति वर्ष देश के लोगों की जो आवश्यकता है एडिबल आयल की उसकी पूर्ति करने के लिए काफी मात्रा में हम फारेन ऐक्सचेंज व्यय करते है और कितने वर्षों से निरन्तर यह प्रक्रिया चली आ रही है । तो इसको प्रायोरिटी पर लाने के संबंध में बताएंगे क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की इंडस्ट्रीज में जितने ऐक्सपैलर लगे हैं उनमें रिकवरी कम होती है । तो यह प्रश्न एक नीति का प्रश्न बन जाता है कि अगर आप अच्छे ऐक्सपैलर लगाएंगे तो ऐक्सट्रेक्शन का रेट या रेशियो बढ़ सकता है । उन्होंने अभी तक इसके लिए रिपोर्ट मंगाई है । इसके लिए इतना फारेन ऐक्सचेंज व्यय किया जा रहा है । मान्यवर हरेक क्षेत्र में भंडारण की व्यवस्था है । हमारी योजना में भी इसको बताया गया है कि इतने करोड़ रुपया खर्च किया गया है । मैं उनसे कहना चाहूंगा व्यापक स्वरूप में, विस्तृत स्वरूप में किस समय अवधि के अंदर यह कदम नयी टेक्नोलोजी के बारे में और उसके अंदर भंडारण की व्यवस्था लाने का प्रयास करेंगे ?

**श्री एच०के०एल० भगत** : नीति तो बिल्कुल स्पष्ट है । नीति यह है कि तेलों को जो बाहर से मंगाने है उसको बाहर से मंगाना कम किया जाए और दूसरे, तेलों के सीड्स देश में ज्यादा पैदा हों यानी तेल ज्यादा पैदा हो और लोगों को तेल

ज्यादा मिले । इसके लिए फार्मर्स को भी एनकरेज किया जाए, मदद की जाए । फार्मर्स को भी, इंडस्ट्री को भी माडर्नाइज किया जाए, उनकी मदद की जाए । नीति बिल्कुल स्पष्ट है । इस नीति पर अमल करने के लिए टेक्नोलोजिकल मिशन बनाया गया है । टेक्नोलोजिकल मिशन कई डायरेक्शंस में काम कर रहा है और कई चीजें उन्होंने की है । यह जो एक्सपैलर्स वगैरह हैं, कुछ उनको इम्पोर्ट करने की इजाजत दी गयी है । मशीनरी को कई तरह से इम्प्रूव करने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं । कितनी समय अवधि में यह काम होगा यह मेरे लिए कहना असम्भव है । टेक्नोलोजिकल मिशन ने डेट लगायी है कि फलाना डेट तक, फलाना ईयर तक होना चाहिए लेकिन मैं नहीं कह सकता कि इसकी प्रोग्रस क्या है । लेकिन इसको प्रियोरिटी दी गयी है। प्रियोरिटी देने की गवर्नमेंट की पालिसी है ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** : माननीय कृषि मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जो इम्प्रूव्ड सीड्स विदेशों से मगा रहे हैं जिसकी इन्होंने चर्चा की है वह भारत की सरकार विदेशी सरकारों से मंगा रही हैं अथवा यहां के प्राइवेट सीड्स ग्रोअर्स विदेशों के प्राइवेट सीड्स कम्पनीज से मंगा रहे हैं ? इसके साथ 'बी' पार्ट यह है कि मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कितने बीज मंगाने की योजना बनाई है और जो बीज मंगायेंगे वह क्या पहले वर्ष ही बांटेंगे ? क्योंकि इससे पेश्तर जब मैक्सिको से 3 वार्फ वैराइटीज आफ सीड्स मंगाये गये थे या चाइना और ताईवान से नये किस्म के पैडी के सीड्स मंगाये गये थे, कई साल तक हिन्दुस्तान की क्लाइमेटिक कंडीशन में, यहां की जमीन में उसको उगा कर देखा गया उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की घोषणा की गयी और डिस्ट्रीब्यूट किये गये ।

**श्री भजन लाल** : सभापति महोदय, तीन बातें वीरेन्द्र वर्मा जी ने पूछी । पहली तो यह कि क्या आयल सीड्स सरकार मंगायेगी या प्राइवेट लोग मगायेंगे ? आयल सीड का सवाल नहीं है । जो सीड्स ग्रोअर्स है वह मंगायेंगे । मोटे अनाज का सीड और फल और सब्जी का बीज ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** : भारत के ?

**श्री भजन लाल** : हां, भारत के और बाहर के भी हमारे देश के किसान भी मंगा सकते है रजिस्ट्रेशन करके । जैसा मैंने कहा उस वक्त आप हाउस में नहीं थे शायद, सीड्स आने के बाद बकायदा उसका टैस्ट किया जायेगा देश के अन्दर । टैस्ट करने के बाद कृषि अनुसंधान यह कहेगा कि ये सीड्स हमारे हिन्दुस्तान की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ठीक हैं वह इसको सर्टीफाई कर देगा तो उस को हिन्दुस्तान की फील्ड में बोने की इजाजत दी जा सकेगी?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** : पहले ही वर्ष में ?

**श्री भजन लाल** : एक साल के बाद । दूसरे, मिकदार का कोई सवाल नहीं है । जितनी सीड्स की लागत यानि खपत होंगी उसी हिसाब से मंगायेंगे ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** : प्राइवेट सीड्स ग्रोअर्स खरीदेंगे या. . .?

**श्री भजन लाल** : जो सीड्स ग्रोअर्स हैं वह लायेंगे ।

**श्री राम चन्द्र विकल** : पहले टैस्ट करा कर लाना चाहिये ।

**श्री भजन लाल** : आप भी किसान हो, वर्मा जी भी किसान हैं और थोड़ा बहुत मैं भी किसान हूं आपकी तरह से । इतनी बात कह सकता हूं कि जो लेने वाले हैं वह बकायदा वहां से पहले टैस्ट करके लाते है । उसके बाद हिन्दुस्तान की धरती पर दाखिल होने से पहले जब वह जहाज से एयरपोर्ट पर आयेगा तो वहां बकायदा हम लेबोरेटरी से टेस्ट करेंगे और टेस्ट होने के बाद आई. सी. ए. आर. में आयेगा और आई.सी.

ए. आर. से टेस्ट करके और अपने फिल्ड में बो करके और यह देखने के बाद कि यह सीड ठीक है या नहीं, और अगर ठीक होगा तो तब सर्टिफाई करके उसको रिलीज करेंगे। इस टैस्टिंग के लिये लेबोरटरी और भी खोलने जा रहे हैं ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** : किस प्राइस पर ?

**श्री भजन लाल** : प्राइस तो आप जानते हैं कि मार्केट प्राइस पर ही होगा क्योंकि उसमें कम्पीटीशन होगा। यह नहीं हो सकता कि एक आदमी को सीड लाने की इजाजत दे और दूसरे को नहीं दें। आज मार्केट में पाच सौ कपड़े की दुकानें है कि लोक ट्राई करके लेते हैं और देखते है कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है। यह तो कम्पीटीशन का सवाल है, एक आदमी का सवाल नहीं है। और ना ही मानोपली होगी।

*204. [*The questioner (Shri Prabhaker Rao Kalvalo) was absent. For answer vide Col.....infra*]

**चीनी का उत्पादन और निर्यात**

***†205. श्री राम नरेश यादव :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन पिछले सभी वर्षों की अपेक्षा अधिक हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चालू वर्ष मे अब तक देश में चीनी की खपत पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक रही है ; यदि हा, तो चीनी की खपत कितनी हुई है ; और

(घ) चालू वर्ष में कितनी चीनी का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत)** :

(क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

चीनी वर्ष, 1987-88 (अक्तूबर, 1987 से सितम्बर, 1988) के दौरान चीनी का उत्पादन सब समय से अधिक 91.03 लाख मीटरी टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष 85.02 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। अक्तूबर, 1988 से प्रारंभ हुये चालू वर्ष 1988-89 के दौरान 31 अक्तूबर, 1988 तक 0.63 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन कर लिया गया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 0.77 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया गया था।

चीनी वर्ष 1987-88 में लगभग 93.00 लाख मीटरी टन चीनी की खपत हुई थी जबकि चीनी वर्ष 1986-87 के दौरान 87.75 लाख मीटरी टन चीनी की खपत की गई थी। वर्ष 1988-89 के दौरान इसमें लगभग 5 से 6 प्रतिशत की और वृद्धि हो सकती है।

फिलहाल चीनी का निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय (10,000 मीटरी टन) और संयुक्त राज्य अमेरिका (5,000 मीटरी टन के आस-पास) के तरजीही कोटों तक ही सीमित है। इसके अलावा, नेपाल, मालदीव जैसे पड़ौसी देशों की मांग को पूरा करने के लिये भी चीनी की कुछ मात्रा का निर्यात किया गया था। चीनी वर्ष 1987-88 के दौरान कुल 0.30 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात किया गया था। 1988-89 के दौरान भी इतनी ही मात्रा निर्यात की जा सकती है।

**श्री राम नरेश यादव** : मान्यवर, माननीय मंत्री जी जानबूझकर जो सवाल मैंने पूछा है उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं

†सभा में यह प्रश्न श्री राम नरेश यादव द्वारा पूछा गया।